

राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश



डीजी परिपत्र सं०-37 /2026
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०

सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ - 226002
फोन नं. 0522-2724003 / 2390240, फैक्स नं. 0522-2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई-मेल : police up@nic.in
वेबसाइट : https://uppolice.gov.in

दिनांक: जुलाई 11, 2026

विषय: मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका बारू सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 04 अन्य (Matter under Article 227 No. 8129 of 2023) में पारित आदेश दिनांक 29.05.2026 का अनुपालन किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

कृपया मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका बारू सिंह एवं अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व 04 अन्य (Matter under Article 227 No. 8129 of 2023) में पारित आदेश दिनांक 29.05.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा० न्यायालय द्वारा लैंगिक अपराध से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं के संरक्षण, गर्भसमापन एवं देखरेख हेतु वृहद निर्देश दिये गये हैं जिसमें विशेषकर पुलिस/गृह विभाग से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुपालन कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

XV- GENERAL DIRECTIONS TO THE FIELD OFFICERS:

133. In all cases where a victim of rape or sexual assault is found to be pregnant, the victim shall, without loss of even a single day, be produced before the concerned Chief Medical Officer along with the report prepared under Section 27 of the POCSO Act, 2012, statements recorded under Sections 180 and 184 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, a copy of the FIR, the Medico-Legal Examination Report of Sexual Violence, and such other relevant documents as may be necessary to assess the physical and mental condition of the victim and to enable an informed decision regarding termination of pregnancy.

133.1 In cases where the victim is a minor and unmarried, the concerned Station House Officer shall immediately inform the Senior Superintendent of Police or the Commissioner of Police, as the case may be, who shall ensure that the victim is produced before all concerned authorities in accordance with the requirements of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, and the POCSO Act, 2012. The concerned Station House Officer shall also record in the General Diary maintained at the police station all steps taken by the police authorities in this regard.

134. If the Chief Medical Officer, or the Chairman of the Child Welfare Committee, fails to attend to the victim or to take the necessary action, such refusal or omission shall also be recorded in the General Diary maintained at the concerned police station. The concerned Station House Officer shall, upon making such an entry, immediately transmit a copy thereof to the Senior Superintendent of Police and the District Magistrate, who

shall take immediate corrective action and record the same in writing within 24 hours of receipt of such information.

135. The concerned Station House Officer shall record in the General Diary the departure and arrival entries of the police personnel deputed to escort the victim for production before the Chief Medical Officer, the Child Welfare Committee, and the jurisdictional Magistrate. The Circle Officer concerned shall countersign such entries on the same day, and the entries shall further be reviewed and countersigned fortnightly by the concerned Senior Superintendent of Police. The Senior Superintendent of Police shall submit a monthly compliance report to the Director General of Police, Uttar Pradesh, consolidating the entries so made across all police stations in the district, for the purpose of centralized monitoring of compliance with these directions.

142. The Chairman of the Child Welfare Committee and the Chief Medical Officer shall ensure that all proceedings conducted by the Child Welfare Committee and the Medical Board in such cases are forwarded to the Secretary, District Legal Services Authority, for supervision and monitoring of compliance. The Secretary, District Legal Services Authority, shall maintain a separate record on a case-by-case basis for monitoring, supervision, and future reference. A copy of all proceedings shall also be forwarded to the concerned District Magistrate for supervision, record-keeping, guidance, and necessary administrative oversight. The Secretary, District Legal Services Authority, shall convene a monthly review meeting with the Chief Medical Officer, the Chairman of the Child Welfare Committee, the District Probation Officer, and one Senior Police Officer of the district, to monitor the status of all pending cases involving minor rape victims who are pregnant or have delivered, and shall submit a monthly report to the Member Secretary, State Legal Services Authority, Uttar Pradesh, for onward transmission to the Principal Secretary, Medical Health and Family Welfare, and the Principal Secretary, Department of Women and Child Development for their record and reference.

146.2 Where justified, the In-charge, District Legal Services Authority, may also recommend attachment of one month's salary of the Chief Medical Officer for utilization towards the welfare of the victim(s), and the initiation of a departmental inquiry. The In-charge, District Legal Services Authority, may, in its discretion, write to the police to initiate a criminal investigation under the relevant provisions of Chapters XII and XIII of the BNSS, 2023. In cases involving the Chairman or a Member of the Child Welfare Committee, the In-charge, District Legal Services Authority, shall write to the Additional Chief Secretary (Home) with a copy to the concerned District Magistrate, recommending that the pecuniary benefits of the defaulting Chairman or Member be withheld or stopped, as the case may be.

उपरोक्त संदर्भ में लैंगिक अपराध से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को चिकित्सीय सुविधा विशेषकर गर्भवती पीड़िताओं के चिकित्सकीय गर्भसमापन (Medical Termination of Pregnancy) हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश दिये जा रहे हैं:-

- 1- बलात्कार अथवा लैंगिक उत्पीड़न के प्रत्येक ऐसे मामले में, जिसमें पीड़िता गर्भवती पाई जाती है, उसे एक भी दिन की देरी किए बिना संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत करते समय उसके साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 27 के अंतर्गत तैयार की गई मेडिको लीगल

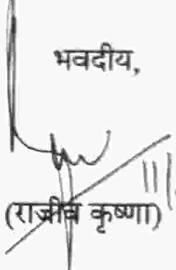
- रिपोर्ट (नाबालिग पीड़िता के मामलों में लागू), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 180 एवं 183 के अंतर्गत दर्ज किए गए बयान, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) की प्रति, लैंगिक हिंसा संबंधी चिकित्सीय-विधिक परीक्षण (Medico-Legal Examination) रिपोर्ट (धारा 184 के अंतर्गत तैयार रिपोर्ट) तथा अन्य आवश्यक अभिलेख संलग्न किए जाएंगे, ताकि पीड़िता की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का समुचित आंकलन किया जा सके और गर्भसमापन के संबंध में सूचित (Informed) एवं उचित निर्णय लिया जा सके।
- 2- ऐसे मामलों में, जहाँ पीड़िता अवयस्क (नाबालिग) एवं अविवाहित हो, संबंधित थाना प्रभारी तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस आयुक्त जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि पीड़िता को गर्भसमापन चिकित्सा अधिनियम, 1971 तथा POCSO Act, 2012 की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।
 - 3- संबंधित थाना प्रभारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई समस्त कार्यवाही का विवरण General Diary में विधिवत अंकित किया जाए।
 - 4- यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा बाल कल्याण समिति, पीड़िता के मामले पर ध्यान देने अथवा आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहते हैं, तो ऐसी अस्वीकृति या चूक का भी उल्लेख संबंधित थाने में संबंधित General Diary में किया जाएगा।
 - 5- संबंधित थाना प्रभारी, ऐसी प्रविष्टि किए जाने के तुरंत पश्चात उसकी एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट उक्त सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई (Corrective Action) सुनिश्चित करेंगे तथा की गई कार्रवाई का लिखित अभिलेख तैयार करेंगे।
 - 6- संबंधित थाना प्रभारी पीड़िता को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बाल कल्याण समिति तथा क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु नियुक्त पुलिसकर्मियों के प्रस्थान एवं आगमन संबंधी प्रविष्टियों को सामान्य डायरी (General Diary) में दर्ज करेंगे।
 - 7- संबंधित क्षेत्राधिकारी उसी दिन इन प्रविष्टियों का प्रति-हस्ताक्षर (Countersign) करेंगे तथा संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक पखवाड़े (Fortnightly) इन प्रविष्टियों की समीक्षा कर उन पर प्रति-हस्ताक्षर किए जाएंगे।
 - 8- संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद के सभी थानों में इस प्रकार की गई प्रविष्टियों का समेकित मासिक अनुपालन प्रतिवेदन (Monthly Compliance Report) तैयार कर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को प्रेषित करेंगे, ताकि इन निर्देशों के अनुपालन की केंद्रीकृत निगरानी (Centralized Monitoring) सुनिश्चित की जा सके।
 - 9- जनपदीय पुलिस प्रमुख का यह दायित्व होगा कि वह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लैंगिक अपराधों से गर्भवती एवं शिशु को जन्म देने वाली नाबालिग पीड़िताओं के मामलों में निगरानी हेतु प्रत्येक माह आयोजित की जाने वाली समीक्षा बैठकों में प्रतिभाग करने एवं संबंधित मामलों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक से अनिम्न स्तर के नोडल अधिकारी नामित करें।
 - 10-मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) अधिनियम, 1971 की धारा 3(2D) के अंतर्गत मेडिकल बोर्ड गठन में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा की गई लापरवाही में आवश्यक होने पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संबंधित जनपद की पुलिस को संदर्भित किये गये मामलों में पुलिस द्वारा बीएनएसएस 2023 के अध्याय XII एवं XIII के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
 - 11-अवगत हों कि प्रदेश के प्रत्येक थाने पर संचालित मिशन शक्ति केन्द्रों का यह प्रमुख दायित्व होगा कि लैंगिक अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं के समुचित पुनर्वास हेतु चिकित्सा विभाग के संबंधित नोडल अधिकारी से आवश्यक समन्वय करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें। साथ ही

मिशन शक्ति केन्द्रों से यह भी अपेक्षा है कि नाबालिग बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु कार्यरत सभी जनपदीय हितधारकों जैसे बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई, वन स्टाप सेन्टर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के संपर्क न० एवं पते रिकार्ड के रूप में रखें एवं आवश्यकतानुसार समन्वय सुनिश्चित करें।

12-उपरोक्त बिंदुओं को मिशन शक्ति केन्द्रों हेतु बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया में भी संशोधन किया जाए एवं किसी भी संशय अथवा विरोधाभास की अवस्था में इस संबंध में जारी किये गये कोई भी पूर्ववर्ती आदेश अतिक्रमित करते हुए उपरोक्त नवीनतम निर्देश प्रभावी माने जायेंगे।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि लैंगिक अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं देखरेख सुनिश्चित करते हुए चिकित्सकीय गर्भसमापन के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही सहित मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार उपरोक्त बिंदुओं पर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(राजनी कृष्णा)

- 1- समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- पुलिस महानिदेशक (रेलवे), 30प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), 30प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), 30प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, (WCSO) 30प्र0 लखनऊ।
- 5- समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, 30प्र0।
- 6- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, 30प्र0।

Bench in "*A through her Father 'F' v. State of U.P. and Others (supra)*" and having regard to the facts brought on record in the present matter, this Court deems it appropriate to issue structured directions coupled with recommendations.

XV- GENERAL DIRECTIONS TO THE FIELD OFFICERS:

133. In all cases where a victim of rape or sexual assault is found to be pregnant, the victim shall, without loss of even a single day, be produced before the concerned Chief Medical Officer along with the report prepared under Section 27 of the POCSO Act, 2012, statements recorded under Sections 180 and 184 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, a copy of the FIR, the Medico-Legal Examination Report of Sexual Violence, and such other relevant documents as may be necessary to assess the physical and mental condition of the victim and to enable an informed decision regarding termination of pregnancy.

133.1 In cases where the victim is a minor and unmarried, the concerned Station House Officer shall immediately inform the Senior Superintendent of Police or the Commissioner of Police, as the case may be, who shall ensure that the victim is produced before all concerned authorities in accordance with the requirements of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, and the POCSO Act, 2012. The concerned Station House Officer shall also record in the General Diary maintained at the police station all steps taken by the police authorities in this regard.

134. If the Chief Medical Officer, or the Chairman of the Child Welfare Committee, fails to attend to the victim or to take the necessary action, such refusal or omission shall also be recorded in the General Diary maintained at the concerned police station. The concerned Station House Officer shall, upon making such an entry, immediately transmit a copy thereof to the Senior Superintendent of Police and the District Magistrate, who shall take immediate corrective action and record the same in writing within 24 hours of receipt of such information.

U

her right to approach the District Legal Services Authority for free legal aid and representation, and whether such aid has been arranged.

138. The Support Person appointed in such cases shall maintain regular contact with the victim and shall visit her at least once every week to provide necessary assistance, counseling, and support. A weekly contact report shall be prepared by the Support Person and submitted to the Chairman of the Child Welfare Committee and to the Secretary, District Legal Services Authority, within two days of each visit. In the event that the Support Person fails to maintain such contact or submit such reports, the Chairman of the Child Welfare Committee shall immediately bring the matter to the notice of the District Probation Officer and the District Magistrate for remedial action, including replacement of the Support Person.

139. The Principal Secretary, Medical Health and Family Welfare, Government of Uttar Pradesh, shall ensure that every district in the State has a duly constituted and functional Medical Board in accordance with Section 3(2-B) and the related provisions of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971. Monthly reports shall be called for from each district regarding the functioning of such Medical Boards, and continuous supervision shall be ensured so that the Medical Boards discharge their duties in letter and spirit. In particular, the Principal Secretary shall ensure that no Medical Board remains without reconstitution for a period exceeding one year, and shall maintain a centralized register of the constitution, reconstitution, and current membership of Medical Boards across all 75 districts of Uttar Pradesh, which shall be updated on a quarterly basis and made available to the Secretary, District Legal Services Authority, of the concerned district.

140. The Principal Secretary, Department of Women and Child Development, Government of Uttar Pradesh, shall ensure that all Child Welfare Committees function strictly in accordance with Government Notifications, the provisions of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, and the Rules framed thereunder. Proper

U

Officer, and one Senior Police Officer of the district, to monitor the status of all pending cases involving minor rape victims who are pregnant or have delivered, and shall submit a monthly report to the Member Secretary, State Legal Services Authority, Uttar Pradesh, for onward transmission to the Principal Secretary, Medical Health and Family Welfare, and the Principal Secretary, Department of Women and Child Development for their record and reference.

XVI- DIRECTIONS FOR THE STATE:

143. The State Government is directed to undertake a comprehensive socio-psychological study, based upon an appropriate survey, concerning the number of rape cases; the number of children born as a consequence of rape; the number of abandoned children; the psychological condition and responses of victims; mechanisms required to address the trauma suffered by victims; the expectations of victims regarding rehabilitation; and all related and ancillary issues. Accordingly, the Chief Secretary, Uttar Pradesh, is hereby directed to constitute an Expert Committee comprising academicians, research scholars, data scientists, policy experts, bureaucrats, and doctors.

143.1 The Expert Committee shall also undertake visits to Child Care Institutions run by both Governmental and Non-Governmental Organizations, CWC, and other academic institutions as may be deemed necessary to achieve the object, to examine the impact of bureaucratic procedures and administrative rigidity upon the implementation of welfare schemes, statutory provisions, rules, regulations, and institutional mechanisms, besides constant in allocation and availability of funds. The State Government shall issue a notification constituting such Expert Committee within a period of three months from the date of receipt of a certified copy of this order. Assistance from Indian Institutes of Management and Indian Institutes of Technology may also be sought to achieve the desired objective. The Expert Committee shall submit its preliminary report within six months of its constitution and a final report

U

compliance with the orders passed by the Supreme Court of India are concerned.

146.1 Any party aggrieved by the conduct of the Chairman or a Member of the Child Welfare Committee, or of the Chief Medical Officer, may approach the *In-charge, District Legal Services Authority*, of the concerned district. The *In-charge, District Legal Services Authority*, after affording the concerned officer or member an opportunity of being heard, and upon being satisfied that there has been negligence, dereliction of duty, non-compliance with Section 3(2-D) of the Medical Termination of Pregnancy Act, 1971, or non-adherence to the relevant provisions of the POCSO Act, 2012, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, or the terms of this order, shall immediately write to the Principal Secretary, Medical Health and Family Welfare, and the Principal Secretary, Department of Women and Child Development, Government of Uttar Pradesh, with a copy to the Chief Secretary, Uttar Pradesh, recommending that immediate steps be taken to relieve the Chief Medical Officer from his official duties.

146.2 Where justified, the *In-charge, District Legal Services Authority*, may also recommend attachment of one month's salary of the Chief Medical Officer for utilization towards the welfare of the victim(s), and the initiation of a departmental inquiry. The *In-charge, District Legal Services Authority*, may, in its discretion, write to the police to initiate a criminal investigation under the relevant provisions of Chapters XII and XIII of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. In cases involving the Chairman or a Member of the Child Welfare Committee, the *In-charge, District Legal Services Authority*, shall write to the Additional Chief Secretary (Home) with a copy to the concerned District Magistrate, recommending that the pecuniary benefits of the defaulting Chairman or Member be withheld or stopped, as the case may be.

146.3 The *In-charge, District Legal Services Authority*, shall conduct monthly visits to and inspections of the records of the Medical Board

U